(b) whether the Enforcement Directorate are in possession of the letter sent by Louis Dreyfus Co. to London based James Greaves and Co. a subsidiary of Greaves Cotton India chaired by Shri L. M. Thapar containing the fact of a cheque sent to Adarsh Saran of James Greaves as part payment against the commission for purchase of edible oil; and

(c) whether any adjudication proceedings have been started with reference to above matter; and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI BRAHM DUTT): (a) Replies have been received and the matter is under adjudication. It may not, therefore, be appropriate to disclose details at this stage.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir. The adjudication proceedings are in progress.

उद्यान लगाने के लिए ब्याजदर

1979. **श्री राधाकिशन मालवीय :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषकों को उद्यान लगाने के लिए सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 10.25 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कृषकों को उद्यानों में पौध रोपने के 5 से 7 वर्षों के बाद फसल प्राप्त होती है और ब्याज की दर अधिक होने के कारण अदायगी योग्य राशि ऋण की मूल राशि से बढ़कर दुगुनी हो जाती है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस अव्यावहारिक प्रावधान के कारण कृषक उद्यान लगाने में रुचि नहीं रखते हैं; और

(घ) क्या वित्त मंत्री को इस वस्तुस्थिति की जानकारी है, यदि हां, तो क्या वह उद्यान लगाने के लिए कृषकों को दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर को घटाकर चार प्रतिशत करने का विचार करेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक बैंक छोटे किसानों से 10% वार्षिक की दर से और बागानों के विकास के लिए सावधि ऋणों के संबंध में अन्य किसानों से 12.5% की दर से ब्याज लेते हैं। ब्याज की ये दरें वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अन्य कृषि कार्यक्रमों पर दिये जाने वाले 15.5% के अधिकतम ब्याज दरों की तुलना में काफी रियायती हैं। इसलिये ब्याज की इन दरों को घटा कर 4 प्रतिशत वार्षिक करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक विकास ने बागानों के विकास के लिए दिये गये ऋणों के संबंध में वापसी अदायगी के बारे में बैंकों के नाम विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किये हैं जिनमें प्रारंभिक अवधि और आवदनी में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा, बागानों में विकास में अन्तर फसल उत्पादन सामान्य बात है इसलिये ऋणकर्ता को बागान की प्रारंभिक अवधि में भी अन्तर फसल उत्पादन की आमदनी से ब्याज और ऋण की किश्तों को चुकाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अतः इन मामलों में जिनमें ऋणकर्ता ब्याज/ऋण की किश्तों की अदायगी में कोई चूक नहीं करता है ब्याज की रकम आवश्यकता से अधिक नहीं बढ़ जाती। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 1984-85 में बागवानी की 576 योजनाएं मंजूर की गई थीं जिनकी संख्या 1985-86 में बढ़कर 698 हो गयी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 1984-85 के दौरान इन योजनाओं के लिये 47 करोड़ रुपये और 1985-86 में 63 करोड़ रुपये की रकम का भुगतान किया गया। उपर्युक्त प्रवृत्तियों से पता चलता है कि किसान बागान और बागवानी की योजनाओं में दिलचस्पी ले रहे हैं

Pay scale of All India services

1980. SHRI NARESH C. PUGLIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Central Government have issued communications/instructions to the State Governments to furnish comments with regard to the proposed pay scales of the three All India Serivces officers;